मांग रिजेक्ट | रूल्स में कोई छूट नहीं देगी फूड मिनिस्ट्री

चीनी खरीदने में राज्यों को छूट नहीं देगी फूड मिनिस्ट्री

[श्रेया जय *नई दिल्ली*]

फूड मिनिस्ट्री ने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के लिए खुद चीनी खरीदने के बदले विकल्प देने की राज्यों की डिमांड ठुकरा दी है। मंत्रालय ने इसे राज्यों के 'आलसीपन' का मामला बताते हुए रूल्स में कोई छूट न देने का इरादा जाहिर कर दिया है।

मिनिस्ट्री के एक सूत्र ने कहा, 'राज्य चीनी खरीदने के लिए आसान पॉलिसी चाहते हैं। राज्यों को पीडीएस के लिए चीनी का कंट्रोल देने का फैसला कैबिनेट का था। इसमें राज्यों के आधार पर बदलाव नहीं किए जा सकते। हम टेंडर प्रोसेस शुरू और चीनी की खरीद शुरू करने के लिए राज्यों पर दबाव डाल रहे हैं।' जून से केंद्र सरकार देशभर में राशन की दुकानों के लिए मिलों से चीनी खरीदने का काम बंद कर देगी। राज्यों को इसे ओपन मार्केट से टेंडर के जरिए खरीदकर सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन की दुकानों के जरिए बेचना होगा। केंद्र ने इन्हें सब्सिडी की रकम मिलेगी।

अभी तक दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल ने ही चीनी खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे चीनी का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने वाले राज्यों ने अभी तक टेंडर जारी नहीं किए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही जम्मू और कश्मीर ने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए समयसीमा बढ़ाने या दूसरे उपाय का आग्रह किया है। अधिकारी ने कहा, 'चीनी के पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए सिस्टम बनाने के मकसद से राज्यों का पर्याप्त समय दिया गया था और उन्हें केंद्र सरकार या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर निर्भर करने के बजाय अब तक इस पर काम शुरू कर देना चाहिए था।'

इकनॉमिक टाइम्स ने मंगलवार को रिपोर्ट दी थी कि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर ने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सरकार की मदद मांगी थी। इन राज्यों ने इसके लिए स्टोरेज की कमी और ट्रांसपोर्टेशन की मुश्किल जैसे कारण बताए थे। मिनिस्ट्री की योजना राज्यों को चीनी के प्रोक्योरमेंट और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन में मदद के लिए सब्सिडी की रकम एडवांस में देने की योजना है। मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्द ही इसके लिए टोकन एमाउंट को हरी झंडी देगी। सूत्र के मुताबिक, 'हम चीनी का पीडीएस प्रोग्राम शुरू करने के लिए रोजाना राज्य सरकारों को पत्र लिख रहे हैं। हम केवल यही आश्वासन दे सकते हैं कि ओपन मार्केट से चीनी खरीदने के लिए सब्सिडी की कुछ रकम दी जाएगी। अब चीनी का दाम नीचे आ चुका है और इसे देखते हुए खरीद में देरी ठीक नहीं है।'

Economic Times

29/5/13